RAJYA SABHA

Friday, the 4th August, 1989/13th Sravana, 1911 (Saka)

The House met at eleven of the clock, **Mr. Chairman** in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

MR. CHAIRMAN: Question No. 261.

श्री राम अवधेश सिंह : सभापति महोदय,***

श्री सभापति : क्वेश्चन-आवर में यह कुछ नहीं होता। इनका कुछ रिकार्ड न किया जाय।

श्री राम अवधेश सिंह : क्वैश्चन आवर में बहुत कुछ होता है।

श्री सभापति : नहीं, कुछ नहीं होगा। आपका कुछ रिकार्ड में नहीं जाएगा, आप जो बोल रहे हैं इर्रेलेवेन्ट, अगेन्सट रूल।

श्री राम अवधेश सिंह : नहीं, ऐसा करने से तो कुछ नहीं चलेगा।

श्री सभापति : चलेगा।

श्री राम अवधेश सिंह : कैसे चलेगा?

श्री सभापति : हाऊस चलेगा। हाऊस को एक आदमी रोक नहीं सकेगा।

श्री राम अवधेश सिंह : एक आदमी हाउस को रोक नहीं सकता?

श्री सभापति : नहीं, आपका कुछ रिकार्ड में नहीं जाएगा।

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राधाकिशन मालवीय) : माननीय चेयरमेन साहब, मेरा आब्जेक्शन है...

श्री सभापति : आपका भी कुछ नहीं है। बैठ जाइये आप। During Question Hour, nothing except questions.

श्री राम अवधेश सिंह :***

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI BINDESHWARI DUBE: Sir, he is disobeying the Chair.

MR. CHAIRMAN: Yes, Question No. 261.

Stoppage of Central aid and grants to the Madhya Pradesh Cooperative Milk Marketing Federation

*261. SHRIMATI RATAN KUMARI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the National Dairy Development Board has stopped all Central aid and grants to the Madhya Pradesh Co-operative Milk Marketing Federation under the Operation Flood-II programme;

(b) if so, the details thereof and the reasons therefor; and

(c) whether Government propose to order an inquiry into the matter?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI BHAJAN LAL): (a) National Dairy Development Board has not discontinued financial assistance to the Madhya Pradesh Dugdha Mahasangh (Sahakari) Maryadit, under the Operation Flood Programme.

(b) and (c) Do not arise.

श्रीमती रत्न कुमारी : सभापति महोदय, पिछले तीन सालों में राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने आपरेशन फ्लड कार्यक्रम के अन्तर्गत मध्य प्रदेश दुग्ध महासंघ को किस प्रकार की और कितनी वित्तीय या किसी दूसरे प्रकार की सहायता दी है?

श्री भजन लाल : सभापति महोदय; मध्य प्रदेश को किसी तरह की भी एड बन्द नहीं की गई है। पूरे मध्यप्रदेश का मैं हाउस को बताना चाहता हूं कि वर्ष 1985 तक आपरेशन फ्लड-टू में 21 करोड़ 86 लाख रुपए दिए गए और अभी जो दिया है आपरेशन फ्लड-थ्री में वर्ष 1985-86 में 9 करोड़ 61 लाख, वर्ष 1986-87 में 4 करोड़ 5 लाख रुपए और 1987-88, 1988-89 में, कुल मिलाकर 17 करोड़ 2 लाख रुपए इन पिछले तीन-चार साल में मध्य प्रदेश को दिए गए हैं।

***Not recorded.

श्रीमती रत्न कुमारी : सभापति महोदय, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा ग्रापरेशन-फ्लड कार्यक्रम के ग्रन्तर्गत जो सहायता दी जाती है, उसके मापदण्ड क्या हैं ? चालू मापदण्ड कब निर्धारित किए गए थे ? क्या सरकार उन मापदण्डों में वर्तमान वित्तीय कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए कोई संशोधन लाने के सुझाव पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ? प्रादेशिक सरकारों को ग्रापरेशन-फ्लड के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री भजन लाल : सभापति महोदय, यह जो मापदण्ड, ग्राप जानते हैं, ग्रलग-ग्रलग हैं, इसका एकाउण्ट किस-किस कार्य के लिए कितना पैसा देना है, उसमें बाकायदा सारे मुल्क में जहां-जहां ग्रापरेशन-फ्लड का काम चालू है, उन सभी को पैसा एलोट करते हैं ग्रौर उन के लिए वह पैसा खर्च करते हैं । जहां तक इन्होंने कहा कि क्या उस नीति में परिवर्तन करने का विचार है, उस नीति में परिवर्तन करने का इसलिए विचार नहीं है कि कोई शिकायत ही नहीं है इसके बारे में । कोई दिक्कत हो, कोई लिखकर दे या उसमें कोई डिफीकल्टी ग्राए तो बताएं हम उसे दूर करेंगे । लेकिन ग्रभी तक इसके बारे में किसी ने कोई डिफीकल्टी जाहिर ही नहीं की है ।

कुमारी सईदा खातून : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि ग्रौर कितने ऐसे राज्य हैं जहां पर कि ग्राप सहायता नहीं दे रहे हैं या विपणन संघ के लिए जो केन्द्रीय सहायता दी जाती है, उसमें कितने ऐसे राज्य हैं जिनमें कि उनकी सहायता बंद कर दी है । उसके क्या कारण हैं ?

श्री सभापति : यह प्रश्न मध्यप्रदेश तक सीमित है ।

कुमारी सईदा खातून : मान्यवर मैं प्रश्न पर ग्रा रही हूं । ट्रक्स में जो दूसरे स्टेट्स से दूध सप्लाय किया जाता है जब वे खाली ट्रक लौटते हैं तो क्या उनमें मध्यप्रदेश के जानवरों के लिए चारा ले जाने की भी कोई व्यवस्था है ?

श्री भजन लाल : सभापति महोदय इसमें चारे का सवाल नहीं है । दूसरे यह सवाल मध्यप्रदेश का ही है। लेकिन मैं माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि ग्रापरेशन-फ्लड के तहत सारे मुल्क में 1195 करोड़ रुपये 1994 तक खर्च होंगे ग्रौर जिस तरह सारे देश में हरित क्रांति ग्राई है, हम चाहते हैं कि उसी तरह सारे मुल्क में श्वेत क्रांति ग्राए ताकि लोगों को स्वच्छ व ताजा दूध मिल सके । ग्रब जहां माननीय सदस्य ने कहा कि दूध वाले ट्रक घास डालकर ले ग्राते हैं, तो उसमें घास डाल ही नहीं सकते । उसके लिए तो टैंक बने हुए हैं । टैंक वाला घास कैसे डालेगा ? उसमें घास ग्राने का सवाल ही नहीं है ।

श्री विठ्ठलराव माधवराव गाधय : माननीय सभापति महोदय, मैं ग्रापके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि मिल्क फ्लड ग्रापरेशन के लिए केन्द्रीय सरकार जो सहायता दे रही है, तो यह वित्तीय सहायता देने के बाद मध्यप्रदेश में मिल्क के प्रोडक्शन में कितनी वृद्धि हुई है। दूसरे इस सहायता के बाद किसानों को दूध के दाम कितने बढ़ाकर दिए गए हैं ?

श्री भजन लाल : सभापति महोदय, इस वक्त मध्यप्रदेश में जो दूध हम को मिल रहा है वह 3 लाख 54 हजार किलो लीटर प्रतिदिन है ग्रौर दूध की बिक्री 2 लाख 35 हजार किलो लीटर प्रतिदिन है । वहां की कैपेसिटी 6 लाख 85 हजार किलो लीटर की है । इसके ग्रलावा जैसाकि मैंने ग्रभी ग्रापसे कहा कि पिछले तीन सालों में हमने मध्यप्रदेश को 17 करोड़ रुपए की सहायता दी है। जहां तक फार्मर्स को देने का ताल्लुक है 3 हजार 465 सोसाइटी . . . (**व्यवधान**)

श्री वीरेन्द्र वर्मा : फार्मर नहीं प्रोडयूसर ।

श्री भजन लाल : वर्मा जी, सुनने की कृपा कीजिये । मैं मिल्क सोसायटी की बात कर रहा हूं । 3 हजार 465 सोसायटीज जिनमें कि 1 लाख 39 हजार मेंबर्स हैं । उन्हें वाकायदा लोन दिया जाता है । एक सोसायटी का 5 लाख तक सहायता के तौर पर पर दिया जाता है कि ताकि उनका पूरा इंतजाम और रख-रखाव ठीक तरह से हो सके . . . (**व्यवधान**)

DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Under the 'Operation Flood' programme to increase the production and procurement of milk, is there any proposal to supply Pomata machine to produce fodder and grass under the expertise of Bharat Krishak Samaj?

सभापति : यह इससे कहां उठता है ?

श्री भजन लाल : सभापति जी, सवाल चारे का नहीं है, दूध का है । लेकिन मुझे जवाब देने में कोई आपत्ति नहीं है । अगर चारा अच्छा पैदा नहीं होगा तो दूध कहां से बनेगा ? हम चाहते हैं कि मुल्क में चारा भी अच्छा पैदा हो । उसके लिये वाकायदा गवर्नमेंट की नीति है । उसके लिये अच्छे मवेशी होने चाहिये । पशुओं की नस्ल सुधारने का भी प्रोग्राम चल रहा है । अच्छा चारा पैदा करने के लिये हम सबसिडी देते हैं ताकि अच्छा चारा पैदा कर के पशुओं को दिया जाय और पशु ज्यादा दूध दे सकें और लोगों की हालत में भी सुधार आ सके ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : दूध की कीमत ।

श्री भजन लाल : आप जानते हैं कि इस समय दूध की कीमत 5 रुपये 92 पैसे है दिल्ली में ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : दिल्ली की बात कर रहे हैं ? उनका क्वेश्चन मध्य प्रदेश का है ।. . . (**व्यवधान**) . . .

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, जहां तक दूध की कीमत का सवाल है गाय और भैंस के दूध की कीमत में थोड़ा अन्तर है । . . . (**व्यवधान**)

श्री सभापति : यह पूछ रहे हैं कि जो दूध पैदा करने वाले किसान हैं, उनको क्या मिल रहा है ? . . . (**व्यवधान**)

श्री अजीत जोगी : क्या यह बात सच है कि हर जगह अलग-अलग भाव है उसका ? . . . (**व्यवधान**)

श्री भजन लाल : सभापति महोदय, मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि अलग-अलग प्रदेशों में अलग-अलग भाव है दूध के, सारे मुल्क में एक जैसा रेट नहीं है । जैसे दिल्ली में 5 रुपये 92 पैसे हमारा एवरेज पड़ता है दिल्ली में और इसी तरह से तकरीबन साढ़े पांच के करीब बाहर का पड़ता है और जो बेचते हैं, वह आप जानते ही हैं कि साढ़े चार रुपये में डी०एम०एस० बेचता पांच रुपये में मदर डेयरी बेचती है और उसमें घाटा उठाना पड़ता है और जो दूध लेने वाले हैं उनको सब्सिडाइज करके देते हैं ।

श्री अजीत जोगी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जो दुग्ध सहकारी संस्थान मध्य प्रदेश में है उनका नियम यह है कि दूध उन्हीं उत्पादकों से लिया जायेगा जो मिल्क रूटस पर आते हैं । मध्य प्रदेश एक आदिवासी बाहुल्य प्रदेश है । जो आदिवासी दुग्ध उत्पादक हैं, वह मिल्क रूटस पर नहीं आते । इस लिये दुग्ध की जो सहकारी संस्थायें बनी हैं उनका लाभ आदिवासी किसानों को, आदिवासी दुग्ध उत्पादकों को नहीं मिल पाता है । तो मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इस विषय में कोई संशोधन किया जायेगा ? साथ ही मैं यह भी जानना चाहूंगा कि जो दूध के भाव

उत्पादकों से लेने के तय किये जाते हैं उसमें और जिस भाव पर दूध कन्जयूमर्स को दिया जाता है उसमें कितना अन्तर है ? इतना अन्तर होने के बावजूद मध्य प्रदेश की ज्यादातर को-आपरेटिव की जो सोसाइटीज और डेयरीज हैं, वे घाटे में चल रही हैं, उज्जैन को छोड़कर बाकी सभी को-आपरेटिव यूनिट्स घाटे में चल रहीं हैं । तो इतना बड़ा अंतर होने के बाद भी इस घाटे को कम क्यों नहीं किया जा रहा है और दूग्ध उत्पादकों से अधिक भाव पर दूध क्यों नहीं लिया जा रहा है ? इस पर भी जरा प्रकाश डालें ।

श्री भजन लाल : सभापति महोदय; फेडरेशन जो दूध लेती हैं, उसको मुनासिब भाव हम देते हैं । ज्यादा भाव जब उनको देते हैं तो आप जानते हैं कि आगे जो कन्जयूम करने वाले हैं, गरीब आदमी, उसके लिये मुश्किल हो जाती है, लेकिन दोनों में अन्तर इतना है कि जैसे मैं दिल्ली की आपको मिसाल देना चाहता हूं ... (**व्यवधान**)

श्री अजीत जोगी : सवाल मध्य प्रदेश का है । ... (**व्यवधान**)

श्री भजन लाल : मैं आपको मिसाल के तौर पर कह रहा हूं कि अकेले डी०एम०एस० में 20-22 करोड़ रुपये का साल भर में घाटा रहता है । इसी तरह से मध्य प्रदेश को भी ले तो जिस रेट पर दूध लेते हैं, उससे कम भाव पर कन्जयूमर्स को देते हैं... (**व्यवधान**)

श्री अजीत जोगी : नहीं, नहीं ऐसा नहीं है । ... (**व्यवधान**)

श्री भजन लाल : उसमें फैट्स का ध्यान भी हम रखते हैं । आप जानते हैं कि हमारा जो स्टैण्डर्ड है फैट्स का वह 3 प्रतिशत होना चाहिये, 3 प्रतिशत से कम नहीं, लेकिन ठीक बात है कि कुछ पाउडर मक्खन को मिलाकर दुग्ध बनाते हैं ताकि जरूरतमन्द लोगों को दूध बढ़िया मिल सके और स्टैण्डर्ड के मुताबिक मिल सके । ... (**व्यवधान**)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप पाउडर का दूध पिला रहे हैं ? ... (**व्यवधान**)

श्री भजन लाल : वह दूध का ही पाउडर है, पाउडर पानी का नहीं है । पाउडर दूध का ही बनता है । उसी के पाउडर और मक्खन मिलाकर के दूध बनाया जाता है । आप जानते हैं कि जब गर्मियों के दिन आते हैं उस वक्त दूध की पूर्ति कम हो जाती है, उस वक्त दूध की पूर्ति करने के लिये, कमी को दूर करने के लिये यह किया जाता है । ... (**व्यवधान**)

श्री सभापति : इनका वक्तव्य यह है कि आप प्रयास करेंगे कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको ठीक से पैसा दें । आप पता लगा लीजिये मध्य प्रदेश से । ... (**व्यवधान**)

श्री भजन लाल : सभापति महोदय, हमारी कोशिश यह रही है कि दूध पैदा करने वालों को अच्छे भाव मिलने चाहिये । लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि आगे भी किसान का ध्यान रखा जायेगा ।

MR. CHAIRMAN: Question No. 262.

*262 (*The questioner (Shri Mohd. Khaleelur Rahman) was absent. For answer Vide cols. .. 29 .. infra*).

MR. CHAIRMAN: Question No. 263.

Handing over the Right to Search for diamonds in Andhra Pradesh to a French Consortium

*263. SHRI DIPEN GHOSH: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have taken a decision to hand over the right to search for diamonds in all